



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

19/9/97

सं० 46]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1997/भाद्र 19, 1919

No. 46]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1997/BHADRA 19, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1997

फा. सं. टी-14012/4/97-टी. ए. एम.पी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, संलग्न अनुसूची के अनुसार एतद्वारा दर की मात्रा में संशोधन करता है।

इस संबंध में किए जाने वाले विनियमों को अंतिम रूप देने के बाद इस दर (इन दरों) की समीक्षा की जाएगी। तथापि, ऐसी समीक्षा, भावी तारीख से ही प्रभावी होगी।

आवेदक

तृतीकोरिन पत्तन न्यास

आदेश

(22 अगस्त, 1997 को पारित)

इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण को तृतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा कार्गो से संबंधित प्रभारों को दस रुपए के अगले अधिक गुणज तक पूर्णांकित करने की अपनाई गई परंपरा अत्यधिक आपत्ति है। यह जानकर आश्चर्य पहुंचा कि यह परंपरा एक दशक से अधिक प्रचलन में है। विदित होता है कि यह पत्तन न्यास द्वारा उठाए गए अनुचित लाभ का मामला है। इसलिए प्राधिकरण इस बात से प्रसन्न है कि पत्तन न्यास पूर्णांकन की शर्त को हटाने के लिए स्वयं इस मामले को प्रस्तुत कर रहा है। फिर भी, इस तथ्य की दृष्टि से यह समझा जाता है कि बिलों को पूर्णांकित करना सप्रयोजन है, बिलों को दस रुपए के अगले अधिक गुणज की अपेक्षा अगले रुपए तक पूर्णांकित करना पर्याप्त होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

THE TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 1997

F. No. T-14012/4/97-TAMP.—In exercise of the powers conferred by section 48 and section 49 of the Major Port Trust Act 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amend the Scale of Rates as in the schedule appended hereto.

The rate(s) is(are) liable to be reviewed after finalisation of the Regulations to be made in this behalf, the effect of such a review will, however, be only prospectively operational.

Applicant

The Tuticorin Port Trust

ORDER

(Passed on this 22nd day of August, 1997)

After considering the facts of the case, the Authority finds the practice adopted by the Tuticorin Port Trust to round off cargo-related charges to the next higher multiple of ten rupees to be highly objectionable. It is shocked to know that this practice has been in vogue for well over a decade. It is seen to be a case of undue advantage taken by the Port Trust. The authority is, thereof, happy to see the Port Trust itself bringing up this case to delete the condition of rounding off. Nevertheless, in view of the fact that there is a purpose in the rounding off bills, it is felt, it will be sufficient if the bills are required to be rounded off to the next rupee rather than to the next higher multiple of ten rupees.

S. SATHYAM, Chairman